

सम्पादकीय

मिसाइल सुरक्षा

बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण में भारत का आगे बढ़ना सुखद और स्वागतयोग्य है। यह देश के लिए खुशखबरी है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को 5,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को नाकाम करने की क्षमता का सफल परीक्षण किया है। बुधवार सुबह से ही बालासोर, ओडिशा के समुद्री तट के आसपास के गांवों में बड़ी हलचल थी कि वैज्ञानिक कोई बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। अनेक गांव खाली करा लिए गए थे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही उन्हें आर्थिक मुआवजा भी दिया गया था। बुधवार देर शाम ही यह स्पष्ट हुआ कि आसमान में उड़ती दुश्मन की मिसाइल को जमीन से मार गिराने की क्षमता का सफल परीक्षण किया गया है। यह भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण की सफलता का अवसर है। मतलब जल्द ही, भारत अपने महत्वपूर्ण शहरों, ठिकानों के आसपास ऐसा मिसाइल सुरक्षा तंत्र स्थापित करेगा, जिससे दुश्मन की ओर से आ रही किसी भी खतरनाक मिसाइल को आसमान में ही नष्ट किया जा सके। अपनी विशाल आबादी की रक्षा के लिए भारत के पास यह सुरक्षा तंत्र होना ही चाहिए। परीक्षण भी बहुत दिलचस्प ढंग से किया गया। पहले एक मिसाइल को दुश्मन की मिसाइल की तरह लगाया गया और उसके बाद जमीन व समुद्र में तैनात भारतीय राडारों ने उस मिसाइल का तत्काल पता लगाया और चार मिनट के भीतर ही जमीन से जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल ने उड़ान भरी और टारगेट से हवा में ऊपर ही जा टकराया। वैसे तो भारत कम दूरी, मध्यम दूरी और बहुत लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में सक्षम है, पर आज के समय में मिसाइल बनाना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक मिसाइलों से बचने की क्षमता विकसित करना भी है। इस परीक्षण में सबसे बड़ी सफलता दुश्मन की मिसाइल का पता लगाने की क्षमता है, जिससे साल 2006 से ही मुकम्मल करने की कोशिश में भारतीय वैज्ञानिक लगे हुए हैं। भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के पहले चरण को पूरा कर चुका है, जबकि दूसरे चरण में नई श्रेणी के इंटरसेप्ट सिस्टम को पुख्ता करने का काम चल रहा है। कम दूरी की मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता भारत के पास पहले से ही है और अब 5,000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को भी नष्ट करने की क्षमता भारतीय सेना की ताकत को नए मुकाम पर पहुंचा देगी। चूंकि भारत की नीति कभी भी पहले हमला करने की नहीं रही है, इसलिए भी उसे मिसाइलों का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। आगे के लिए यह मानकर चलना चाहिए कि जब भी युद्ध होगा, भारत का मुकाबला मिसाइलों की बौछार से होगा, अतः उनसे सुरक्षा का कवच तैयार करना समय की मांग है। भारत ने एस-400 नाम का मिसाइल सुरक्षा कवच रूस से लिया है। अभी कुछ और की आपूर्ति होनी है। वास्तव में, हमें अपना पुख्ता मिसाइल सुरक्षा कवच विकसित करना चाहिए। ताजा सूचना है, युद्ध में लगा रूस अब भारत की ज़रूरतों पर भी ध्यान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा के बाद रक्षा आपूर्ति में तेजी आ रही है। रूस हमें 120 मिसाइलें देने वाला है। ये सारी मिसाइलें हमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास तैनात करनी होंगी। बहरहाल, भारतीय रक्षा पंक्ति का भविष्य उज्वल है और इसके लिए हमें पूरी तेजी से काम करना चाहिए।



■ आलोक जोशी

बजट से एक दिन पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत के कॉलेजों से हर साल जो छात्र ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उनमें से सिर्फ 51.25 प्रतिशत नौजवान ही नौकरी पाने के लायक हैं। इसका मतलब है कि कॉलेज से निकल रहे हर दो में से एक छात्र को नौकरी मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। इसी सर्वेक्षण में दूसरा आंकड़ा यह भी था कि अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे तालमेल बैठाने के लिए भारत में हर साल करीब 78.5 लाख रोजगार पैदा करने होंगे। नई नौकरियां पैदा करने का यह काम 2036 तक, यानी अगले बारह साल तक जरूरी होगा। कुल मिलाकर, करीब दस करोड़ नए रोजगार! बजट में वित्त मंत्री ने अपनी जो नौ प्राथमिकताएं गिनाईं, उनमें पहले नंबर पर खेती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर रोजगार व कौशल के साथ ही तीसरे नंबर पर भी समावेशी मानव संसाधन था। यानी, रोजगार और नौजवानों पर असर डालने वाले फैसले। वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर पांच योजनाओं का एलान किया है, जिनसे कुल मिलाकर चार करोड़ दस लाख नौजवानों को फायदा होगा। सरकार इन पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार के मोर्चे पर जो पहला एलान किया, वह है 'एंग्लोमेंट लिंकड इन्सैटिव', यानी रोजगार पैदा करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र को मदद देगी। इस योजना के तीन हिस्से हैं। पहली योजना है, पहली नौकरी पाने वालों को उनकी एक महीने की तनखाह सरकार से मिलेगी। यह राशन और गैस की सब्सिडी की तरह डीबीटी मॉडल पर काम करेगा। इसका मतलब है कि पैसा सीधे इन लोगों के खाते में जाएगा। यह रकम तीन किस्तों में दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 15 हजार रुपये ही एक व्यक्ति को मिलेंगे। हालांकि, एक लाख रुपये महीने तक वेतन पाने वाले लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अनुमान है कि दो करोड़

विशेष

नौकरी देने-दिलाने की जरूरी कवायद

रोजगार में स्किल या कौशल का संकट दूर करने के लिए एक और बड़ा एलान है, इंटरनशिप स्कीम। इसके तहत देश की पांच सौ बड़ी कंपनियों में एक करोड़ नौजवानों के लिए इंटरनशिप का रास्ता खुलेगा। उन्हें हर महीने पांच हजार रुपये का स्टैंडपेंड और छह हजार रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी। कंपनियां इस खर्च का दसवां हिस्सा और ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च अपने सीएसआर बजट से ले सकेंगी। जाहिर है, योजनाएं तो अच्छी हैं, मगर अब चुनौती है इन्हें साकार करने की।



दस लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी ईपीएफओ योजना का सदस्य बने और उसके रिकॉर्ड के मुताबिक, यह उसकी पहली नौकरी हो।

दूसरी योजना खास तौर पर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कारखानों में काम करने वालों के लिए है। इरादा है कि मैनुफैक्चरिंग सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र) में नए लोगों के लिए ज्यादा रोजगार पैदा हो। वजह शायद यह भी है कि बरसों से मैनुफैक्चरिंग सेक्टर ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह इस मामले में पिछड़ता दिख रहा है। नई योजना के तहत सरकार इस क्षेत्र में नौकरी पाने वाले लोगों और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को एक निश्चित दर से पहले चार साल तक उनके ईपीएफओ खाते में योगदान में मदद करेगी। यह योजना की उर्ध्व लोगों पर लागू होगी, जिनकी यह पहली नौकरी है। इससे तीस लाख नौजवानों और उन्हें रोजगार देने वालों को फायदा पहुंचेगा।

तीसरी योजना खासकर रोजगार देने वालों पर नजर रखकर बनाई गई है। किसी भी क्षेत्र या उद्योग में एक लाख रुपये महीने की तनखाह तक की नई नौकरी देने वालों को

इस योजना में गिना जाएगा। सरकार हर नए कर्मचारी के लिए नियोजता के खाते से जाने वाली रकम में से हर महीने तीन हजार रुपये तक उन्हें देगी। स्कीम का फायदा वे दो साल तक ले पाएंगे। अनुमान है, ऐसे पचास लाख नए लोगों को रोजगार मिल जाएगा।

ये तीनों स्कीम जहां एक बड़ा रास्ता खोल रही हैं, वहीं यह एक बड़ी चुनौती की निशानदेही भी कर रही हैं। अभी हाल में मुंबई और सूरत में मुड़ी भर नौकरियों के लिए जिस तरह हजारों की भीड़ उमड़ी, वह दिखा रहा है कि नौकरी इस देश में कितनी बड़ी नियामत है। यह बात भी लगभग साफ हो चुकी है कि अब सरकारें एक सीमा से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकतीं। मगर निजी क्षेत्र भी कितनी नौकरियां दे पाएगा, यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। अगर निजी क्षेत्र को भी अपने काम के लोग नौकरी पर रखने के लिए सरकार से ही सहारा चाहिए, तो आगे क्या होगा? इसी के साथ सवाल उठा कि लोगों को नौकरी पर रखकर कर्मचारी और कंपनी, दोनों ने सरकार से मदद ले ली और फिर उसकी नौकरी खत्म हो गई, तब क्या होगा? हालांकि, बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी सफाई आ गई और बताया गया कि अगर

नौकरी एक साल से पहले खत्म हो गई, तो कंपनी को वह इन्सैटिव की रकम सरकार को लौटानी पड़ेगी। जाहिर है, ऐसा तभी होगा, जब कंपनी को नए कर्मचारी काम के नहीं लगेंगे या फिर उन्हें कोई बेहतर काम मिल जाएगा। बेहतर काम के लिए जाना तो अच्छी बात है, मगर दूसरी सूत्र पैदा न हो, इसके लिए भी वित्त मंत्री ने बजट में इंजाम किया है। वह है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की चौथी स्कीम।

इसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र से मिलकर अगले पांच साल में बीस लाख नौजवानों को तरह-तरह के कौशल या स्किल की ट्रेनिंग देने का इंजाम करेगी। इसके लिए देश भर में एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या आईटीआई-उनत किए जाएंगे और वहां छात्रों को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं, छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के लिए 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर सरकारी गारंटी भी दी जाएगी। देश में ही पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज सस्ती दरों पर दिया जाएगा। और जो लोग नौकरी की जगह अपना रोजगार करने की राह पर निकल पड़े हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा एलान है। जिन लोगों ने तरुण श्रेणी में मुद्रा लोन लेकर चुना दिया है, उनके लिए नया मुद्रा लोन लेने की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दी गई है।

रोजगार में स्किल या कौशल का संकट दूर करने के लिए एक और बड़ा एलान है, इंटरनशिप स्कीम। इसके तहत देश की पांच सौ बड़ी कंपनियों में एक करोड़ नौजवानों के लिए इंटरनशिप का रास्ता खुलेगा। उन्हें हर महीने पांच हजार रुपये का स्टैंडपेंड और छह हजार रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी। कंपनियां इस खर्च का दसवां हिस्सा और ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च अपने सीएसआर बजट से ले सकेंगी। जाहिर है, योजनाएं तो अच्छी हैं, मगर अब चुनौती है इन्हें साकार करने की।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रदेश

निजी मालिकों की लोक परिवहन सेवा की बसों का विस्तार करने का जताया विरोध

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर

रोडवेज कर्मचारियों ने डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनस खान का फूंका पुतला



कर्मचारी-अधिकारी उनसे खासे नाराज हैं। जयपुर में चौमू हाऊस एरिया में पुराने केंद्रीय कार्यशाला

के सामने से बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों ने यूनस खान का पुतला लेकर उनके विरुद्ध नारे

लगाते हुए रोडवेज मुख्यालय तक रैली निकालकर सभा की। सभा को राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के संयोजक एमएल यादव, एटक के महासचिव धर्मवीर चौधरी, सीटू के महासचिव किशन सिंह राठी, इटक के संयोजक आलोक दुबे, एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद चौधरी एवं कल्याण समिति के नेता ताराचंद जैन ने सम्बोधित करते हुए यूनस खान द्वारा विधानसभा में दिए गए रोडवेज विरोधी बयान की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है कि रोडवेज की आय में व्यापक बढ़ोतरी के लिए बिना किसी देरी के समुचित उपाय किए जाएं। सभा के बाद कर्मचारियों के नारों के बीच यूनस खान का पुतला फूंका गया।

आईएसएनआर मिड टर्म सीएमई कल ब्रेन स्टोक के इलाज पर होगी चर्चा

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर। निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल (एनएचबीएच) और निम्स हॉस्पिटल के न्यूरोइंटरवेंशन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग द्वारा रविवार को होटल ललित में 'आईएसएनआर मिड टर्म सीएमई' का आयोजन किया जाएगा। इसमें राजस्थान और अन्य राज्यों के 250 से अधिक न्यूरोइंटरवेंशनलिस्ट, रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के डॉक्टर और रेजिडेंट्स के भाग लेने की उम्मीद है। इस मिड टर्म इवेंट की थीम ब्रेन स्टोक-न्यूरोइंटरवेंशन-रेवोल्यूशन इन सेविंग लाइव्स रखी गई है। सम्मेलन में व्याख्यान, भाषण, पैनल चर्चा, गतिशील बातचीत, उपदेशात्मक व्याख्यान, लाइव इन बॉक्स वीडियो और अन्य न्यूरो एक्टिविटीज शामिल होंगी। विशेषज्ञों द्वारा ब्रेन स्टोक का इलाज, न्यूरो इंटरवेंशन और ब्रेन की एंजियोप्लाफी जैसे विषयों पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिए जाएंगे। कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉ. शैलेश गायकवाड़, आयोजन सचिव डॉ. मदन मोहन गुप्ता, संरक्षक प्रो. डॉ. बीएस तोमर सहित सह संरक्षक डॉ. संजीव शर्मा, प्रो. अमरीका सिंह, डॉ. ईशान शर्मा, डॉ. पंकज सिंह, डॉ. निरंजन खण्डेलवाल, मनीषा चौधरी एवं अन्य गणमान्य जन मौजूद रहेंगे। डॉ. मदन मोहन गुप्ता ने बताया कि इस तरह की डेडिकेटेड ब्रेन स्टोक न्यूरो इंटरवेंशन जयपुर में पहली बार आयोजित हो रही है, इसमें एडवांस्ड मैकेनिकल मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी और न्यूरो इंटरवेंशन के बारे में चर्चा की जाएगी।

बालाजी महाराज मेले पर परसनेऊ स्टेशन पर गाड़ियों का अस्थाई ठहराव

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु बालाजी दादोजी महाराज मेले के अवसर पर बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-बीकानेर व प्रयागराज-लालगढ़-प्रयागराज रेलसेवाओं का परसनेऊ स्टेशन पर 23.08.24 व 24.08.24 को अस्थाई ठहराव दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 22471, बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस रेल सेवा जो दिनांक 23.08.24 व 24.08.24 को बीकानेर से रवाना होगी, वह परसनेऊ स्टेशन पर 10.55 बजे आगमन एवं 10.57 बजे प्रस्थान करेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22472, दिल्ली सराय रोहिल्ला-बीकानेर एक्सप्रेस रेल सेवा जो 23.08.24 व 24.08.24 को दिल्ली सराय रोहिल्ला से रवाना होगी, वह परसनेऊ स्टेशन पर 14.18 बजे आगमन एवं 14.20 बजे प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 12458, बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस रेल सेवा जो 23.08.24 व 24.08.24 को बीकानेर से रवाना होगी, वह परसनेऊ स्टेशन पर 23.55 बजे आगमन एवं 23.57 बजे प्रस्थान करेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 12457, दिल्ली सराय रोहिल्ला-बीकानेर एक्सप्रेस रेल सेवा जो 22.08.24 व 23.08.24 को दिल्ली सराय रोहिल्ला से रवाना होगी, वह परसनेऊ स्टेशन पर 05.20 बजे आगमन एवं 05.22 बजे प्रस्थान करेगी।

एलियांस हैकथॉन-24 : एआई इनोवेशन के लिए आए इनोवेटिव आइडिया

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

एलियांस हैकथॉन-24 एक अद्भुत 24 घंटे का कोडिंग मैराथन है, जो अंतरराष्ट्रीय मेटर्स द्वारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इनोवेशंस को डेडिकेटेड है। इस कार्यक्रम का आयोजन एलियाआईटी सॉल्यूशंस द्वारा शुक्रवार सुबह 11 बजे जयपुर के राजापार्क स्थित, एलियाआईटी सॉल्यूशंस डेवलपमेंट सेंटर में किया गया, जो शनिवार को सुबह 11 बजे तक चलेगा। यह जानकारी एलियाआईटी सॉल्यूशंस की सीईओ मेधा भाटिया ने दी। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के टेक इनोवेटर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसका समापन चार फाइनलिस्ट टीमों द्वारा प्रभावशाली प्रेजेंटेशन्स की एक श्रृंखला के साथ हुआ। इस कार्यक्रम ने वास्तविक दुनिया के चैलेंजिस का समाधान करने में कोलेबोरेशन, लर्निंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की शक्ति पर प्रकाश डाला। हम इन समाधानों को और विकसित होते हुए देखना चाहते हैं और समाज पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखने के लिए उत्सुक हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 50+ से अधिक प्रतिभाशाली अंतरराष्ट्रीय मेटर्स ने फोकस एआई आधारित सॉल्यूशंस-4 अर्सेनिंग सॉल्यूशंस प्रस्तुत हुए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एआई संचालित कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्टिंग टूल, एआई मॉडल के आधार पर फोटो और रिपोर्टिंग के लिए एआई सुझाव मॉडल, एआई संचालित सर्वे क्रिएशन टूल और कार रेंटल एआई सक्षम टूल आदि प्रस्तुत हुए।



जेईसीआरसी के जेयू-ओरिएंट 2024 के जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

जेईसीआरसी के जेयू-ओरिएंट 2024 का तीसरा दिन देश की जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत। टेड स्पीकर डॉ. विजेंद्र सिंह चौहान, पब्लिक पालिसी लीडर, विनीता हरिहरन, आर. सिद्धार्थ, करियर डिप्लोमाके चैट सेशन में स्टूडेंट्स ने जीवन की पाठशाला के अनमोल मंत्र सीखे। डॉ. विजेंद्र सिंह चौहान ने अपने सम्बोधन में कहा कि जब आप विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो आपके पास एक दृष्टिकोण होता है। विश्वविद्यालय वह जगह है जहां असीम संभावनाएं होती हैं। यहां आपको सांस्कृतिक विविधता का अनुभव मिलता है और आप इस विविधता को अनुभव और पोषित करते हैं जो आपके भविष्य में मदद करेगी। ब्यूरोक्रेसी में ईमानदारी की साधना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अच्छे ईमान बनने के लिए बुनियादी स्तर की ईमानदारी आवश्यक है। एक ईमानदार व्यक्ति बनने से आप न केवल बेहतर ईमान बनते हैं, बल्कि बेहतर रिश्ते भी बनाते हैं, यदि आपको बड़ी सफलता चाहिए, तो इसका सरल तरीका है कि आप ईमानदार बनें। पब्लिक पालिसी लीडर, विनीता हरिहरन, ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप समाज में कितना योगदान देते हैं। देश के निर्माण और विकास के लिए आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है।

बड़ी सफलता चाहिए तो आप ईमानदार बनें : चौहान

